विचार बिन्दु

स्वयं को बदल दो, भाग्य बदल जायेगा –कहावत

एक जिला एक उत्पाद नीति राजस्थान : लोकल टू ग्लोबल

राजस्थान की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एक जिला एक उत्पाद (ODOP) नीति एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। यह नीति स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को वैश्विक पटल पर चमकाने का माध्यम बन गई है। राजस्थान सरकार ने इस नीति को अपनाते हुए रेगिस्तानी राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को आर्थिक शक्ति में बदलने का संकल्प लिया है। लोकल टू ग्लोबल का मंत्र यहां साकार हो रहा है, जहां जिले के पारंपरिक उत्पाद न केवल स्थानीय बाजारों में मजबूत हो रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। राजस्थान, जो अपनी रंगीन संस्कृति, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों के लिए जाना जाता है, इस नीति के माध्यम से आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में शुरू की गई ODOP योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्टता को पहचानना और उसे बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार ने इसे तुरंत अपनाया और 2021 से राज्य स्तर पर इसे लागू किया। राजस्थान सरकार ने इसे प्राथमिकता दी। राज्य में 33 जिलों में से प्रत्येक के लिए एक प्रमुख उत्पाद चुना गया, जो स्थानीय संसाधनों, परंपराओं और बाजार क्षमति पर आधारित है। उदाहरणस्वरूप, बाड़मेर का लेहरीया प्रिंट, जोधपुर का मोतीकारी कढ़ाई, जयपुर का हस्तशिल्प, उदयपुर का मिनिएचर पेंटिंग और अलवर का मोर पंख शिल्प इनकी बानगी भर हैं। ये उत्पाद न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि रोजगार सृजन के स्त्रोत भी बन रहे हैं।

राजस्थान सरकार के प्रयासों ने ODOP को ठोस जमीन प्रदान की है। उद्योग विभाग, RIICO और राजस्थान छोटे उद्योग एवं निर्यात निगम (RIICO) ने संयुक्त रूप से कार्य योजना बनाई। प्रत्येक जिले में ODOP हब स्थापित किए गए, जहां कारीगरों को प्रशिक्षण, डिजाइन सुधार, पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा दी जाती है। सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया, जिसमें सब्सिडी, मशीनरी खरीद और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर जोर दिया गया। आर्ट ऑफ राजस्थान पोर्टल लॉन्च किया गया, जो ODOP उत्पादों को ऑनलाइन बेचने का केंद्र है। इसके अलावा, राजस्थान ग्रांडीयोज ब्रांड बनाया गया, जो वैश्विक बाजारों में राजस्थानी उत्पादों की एकरूप छवि प्रस्तुत करता है।

ODOP के तहत राजस्थान के जिलों ने अपनी विशिष्टताओं को निखारा है। बाड़मेर में लेहरीया और बंधेज साड़ियां अब दुबई और अमेरिका के बाजारों तक पहुंच रही हैं। यहां 500 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया, जिससे उनका उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा। जोधपुर का ब्लू सिटी अब मोतीकारी फर्नीचर के लिए जाना जाता है। सरकार ने यहां ODOP क्लस्टर विकसित किया, जहां डिजाइन वर्कशॉप आयोजित होते हैं। जयपुर का ब्लू पॉटरी और कीमती पत्थर उद्योग को बढ़ावा मिला। अलवर के हस्तशिल्प और दौसा के आंवला उत्पाद ने जैविक खेती को प्रोत्साहित किया। कोटा का कोटा स्टोन और बांसवाड़ा का बांस उत्पाद भी चमक रहे हैं। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे स्थानीय संसाधन वैश्विक अवसर बन रहे हैं।

यह नीति स्थानीय कारीगरों, किसानों और छोटे उद्यमियों को वैश्विक पटल पर चमकाने का माध्यम बन गई है। राजस्थान सरकार ने इस नीति को अपनाते हुए रेगिस्तानी राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को आर्थिक शक्ति में बदलने का संकल्प लिया है। लोकल टू ग्लोबल का मंत्र यहां साकार हो रहा है, जहां जिले के पारंपरिक उत्पाद न केवल स्थानीय बाजारों में मजबूत हो रहे हैं,

सरकार ने मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दिया। इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (ODOP) में राजस्थान पवेलियन ODOP उत्पादों का केंद्र बना। दुबई एक्सपो 2020 और कंबोडिया के अंतरराष्ट्रीय मेलों में भागीदारी से निर्यात बढ़ा। ई-कॉमर्स के माध्यम से अमेजन, फ्लिपकार्ट और ईटीसी प्लेटफॉर्म पर ODOP स्टोर खोले गए। वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत सोशल मीडिया कैंपेन चलाए गए, जिसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों व्यूज मिले। राजस्थान पर्यटन के साथ लिंकेज बनाकर हैंडीक्राफ्ट टूर्स शुरू किए, जहां पर्यटक सीधे कारीगरों से उत्पाद खरीदते हैं। इससे न केवल बिक्री बढ़ी, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन को भी बल मिला।

प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट ध्अ्ध्ड्ढका मजबूत आधार हैं। राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (RSLDC) ने 10,000 से अधिक कारीगरों को डिजिटल मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग का प्रशिक्षण दिया। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए स्वयं सहायता समूहों (SHG) को जोड़ा गया। उदाहरण के लिए, उदयपुर के बांसवाड़ा में आदिवासी महिलाओं को बांस उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण देकर बाजार से जोड़ा गया। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। सरकार ने जीआई टैग आवेदन तेज किए, जैसे बाड़मेर का बंधेज और कोटा का डोरिया साड़ी को मान्यता मिली। यह ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ।

चुनौतियां भी हैं, जिन्हें सरकार दूर करने में जुटी है। कच्चे माल की कमी, बाजार पहुंच और तकनीकी पिछड़ापन प्रमुख हैं। रेगिस्तानी जलवायु में रंगाई-प्रक्रिया प्रभावित होती है, इसलिए सोलर ड्रायर और वाटर हार्वेस्टिंग योजनाएं शुरू की गईं। डिजिटल साक्षरता के अभाव को दूर करने हेतु मोबाइल वैन भेजी जा रही हैं। कोविड-19 के बाद सप्लाई चेन बाधित हुई, लेकिन ODOP ने इसे अवसर में बदला परिणामस्वरूप, 2023-24 में ODOP से 500 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जो पिछले वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है। 50,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।

ODOP ने राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया है। पीढ़ियों से चली आ रही कला, जैसे जोधपुर की साफा बांधन कला या चित्तौड़गढ़ की तलवार नक्काशी, अब विलुप्त होने के कगार से लौट रही है। युवा पीढ़ी को जोड़ने हेतु स्कूलों में वर्कशॉप आयोजित हो रहे हैं। यह नीति सतत विकास का प्रतीक है, जहां पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों को प्राथमिकता दी जा रही है। जैविक रंगों का उपयोग और प्लास्टिक-मुक्त पैकेजिंग से ग्रीन ब्रांडिंग हो रही है। वैश्विक स्तर पर सस्टेनेबल हैंडीक्राफ्ट की मांग में राजस्थान अव्वल है।

भविष्य की योजनाएं उत्साहजनक हैं। सरकार 2026 तक 10,000 करोड़ का निर्यात लक्ष्य रख रही है। ODOP पार्क विकसित हो रहे हैं, जहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एआई और ब्लॉकचेन से ट्रेसिबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि उत्पाद की प्रामाणिकता बनी रहे। स्टार्टअप इंडिया से जोड़कर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां, जैसे जापान और यूरोप के ब्रांड्स के साथ, नए द्वार खोल रही हैं। राजस्थान का ODOP मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा है।

एक जिला एक उत्पाद नीति ने राजस्थान को साबित कर दिया कि स्थानीयता वैश्विकता का आधार बन सकती है। यह न केवल आर्थिक उन्नति ला रही है, बल्कि सांस्कृतिक गौरव को भी पुनर्जीवित कर रही है। कारीगरों की मुस्कान, ग्रामीणों की समृद्धि और राज्य की प्रगति इसकी साक्षी हैं। लोकल टू ग्लोबल का सपना साकार हो रहा है, और राजस्थान इसकी अगुवाई कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह नीति भारत की आर्थिक शक्ति को नई दिशा देगी।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉरपोरेट सलाहकार

दिन में बिजली और सौर ऊर्जा क्रांति से सशक्त होता किसान

पुष्पेंद्र सिंह राणावत

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के सभी जिलों में वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी संकल्प लेकर इसे तेजी से क्रियान्वित करवा रहे हैं। दौसा एवं करौली जिले के कृषि उपभोक्ताओं को खेती के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली सुलभ कराने के साथ ही अब कुल 24 जिलों के कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली सुलभ करवाई जा रही है।

अब जयपुर डिस्कॉम के 9 जिलों- धौलपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, जयपुर, डीग, दौसा, करौली एवं भरतपुर के किसानों को सिंचाई के लिए दिन के दो ब्लॉक में बिजली उपलब्ध हो रही है। इसी तरह अजमेर डिस्कॉम के 12 जिलों-अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना-कुचामन, उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, बांसवाड़ा, झुन्झुनूं, सीकर, चित्तौड़गढ़ एवं डूंगरपुर तथा जोधपुर डिस्कॉम के 3 जिलों-जालौर, सिरोही एवं पाली में भी कृषकों को दिन के दो ब्लॉक में आपूर्ति की जा रही है।

जयपुर डिस्कॉम ने विद्युत तंत्र को मजबूत करने के लिए दौसा जिले में 33 केवी के 18 तथा करौली जिले में 33 केवी के 6 नए ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए हैं। इसके साथ ही दौसा में 33 केवी के 47 सब स्टेशनों पर ट्रांसफार्मरों में 128.95 एमवीए की क्षमता वृद्धि की गई है। करौली में 33 केवी के 15 सब स्टेशनों पर 49.45 एमवीए की क्षमता बढ़ाई गई है। दोनों जिलों में पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए एवं कम्पोनेंट-सी में 32 मेगावाट क्षमता के 17 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। दौसा जिले के 52,460 तथा करौली जिले के 35,341 कृषि उपभोक्ता अब दिन में बिजली आपूर्ति का उपभोग कर सकते हैं।

कृषकों को इन जिलों में कड़ाके की सर्दी एवं बारिश में रात्रि के समय सिंचाई करने की मजबूरी नहीं रहेगी। इन 24 जिलों में दिन में बिजली मिलने से किसान सुरक्षित वातावरण में, बेहतर निगरानी के साथ अपनी फसल की सिंचाई कर सकते हैं। दिन में बिजली उपलब्ध कराए जाने वाले जिलों में हो रहे निरन्तर विस्तार से स्पष्ट है कि राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे पूरे राज्य में लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2027 तक सभी जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

इस परिवर्तन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मजबूत किए गए विद्युत ढांचे की है। नए ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना, ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि और वितरण नेटवर्क के विस्तार ने इस योजना को व्यवहारिक रूप दिया है। राज्य सरकार ने नीति बनाकर इसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना भी तैयार की है।

इस पूरी पहल का सबसे सशक्त आधार केवल पारंपरिक बिजली आपूर्ति नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा के रूप में उभरती नई शक्ति है। पीएम-कुसुम योजना ने इस बदलाव को गति दी है और राजस्थान को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया है।राज्य में अब तक लगभग 1961 मेगावॉट क्षमता के 940 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इनमें से अधिकांश पिछले दो वर्षों में ही पूरे हुए हैं। राजस्थान ने अब सूर्य की ऊर्जा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया है। कुसुम योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसने किसान की भूमिका को पूरी तरह बदल दिया है। किसान केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं रहा, बल्कि वह ऊर्जा उत्पादक भी बन गया है। खेतों में लगे सोलर पंपों के माध्यम से किसान दिन में सिंचाई कर रहा है, डीजल पर उसकी निर्भरता समाप्त हो रही है और उत्पादन लागत कम हो रही है। अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर किसान आय का एक नया स्त्रोत भी प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार, अन्नदाता अब ऊर्जादाता के रूप में भी उभर रहा है।

इस परिवर्तन का राज्य की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संरचना पर भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पन्न बिजली सीधे स्थानीय ग्रिड से जुड़ने के कारण ट्रांसमिशन लॉस में कमी आई है और बिजली वितरण अधिक प्रभावी हुआ है। लगभग 90 हजार करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ राजस्थान का ऊर्जा क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। महंगे थर्मल पावर पर निर्भरता घट रही है और स्वच्छ ऊर्जा का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है, जल संसाधनों पर दबाव कम हो रहा है और वायु प्रदूषण घट रहा है। यह योजना केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी सशक्त माध्यम है। ग्रामीण विकास के संदर्भ में भी इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सोलर संयंत्रों की स्थापना, संचालन और रखरखाव ने नए रोजगार अवसर पैदा किए हैं। युवाओं को तकनीकी क्षेत्रों में काम करने के अवसर मिल रहे हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई गतिशीलता आई है। अब खेती फसल उत्पादन और ऊर्जा उत्पादन के साथ बहुआयामी गतिविधि बन चुकी है।

राज्य सरकार ने इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी कई नवाचार किए हैं। सौर संयंत्रों की स्वीकृति, ऑनलाइन एग्रीमेंट, मीटर टेस्टिंग और ग्रिड कनेक्टिविटी जैसी प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया गया है। वन-स्टॉप समाधान प्रणाली ने किसानों और निवेशकों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाया है। इससे परियोजनाएं तेजी से धरातल पर उतर रही हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान गुणवत्ता की बिजली आपूर्ति, तकनीकी रखरखाव, किसानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण और सौर परियोजनाओं के विस्तार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। समग्र रूप से देखा जाए तो राजस्थान में दिन में बिजली आपूर्ति और पीएम-कुसुम योजना के समन्वय का मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता और तकनीकी नवाचार के बेहतर समन्वय से राजस्थान अब प्रगति के नये सोपान अर्जित कर रहा है। अब राजस्थान का किसान अंधेरे में संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि उजाले में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किसान बन रहा है। खेतों में फसल के साथ ही ऊर्जा भी उग रही है और यही एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राजस्थान की पहचान है।

–पुष्पेंद्र सिंह राणावत,
विधायक एवं पूर्व ऊर्जा मंत्री

सरकारी भर्ती में कट ऑफ से आगे की कहानी : जहां प्रतिभा हारती है और सिस्टम चूकता है

सुनील दत्त गोयल

भारत में सरकारी नौकरी केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, प्रतिष्ठा और स्थायित्व का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों युवा अपनी उम्र के सबसे उत्पादक वर्ष इस तैयारी में लगा देते हैं – कोचिंग, किराया, किताबें, परीक्षा शुल्क और सबसे बढ़कर मानसिक दबाव – इन सबका बोझ उठाते हुए। यह केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि जीवन का एक लंबा संघर्ष बन जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष अंततः न्यायपूर्ण अवसर में बदलता है, या फिर एक ऐसी प्रणाली में फँस जाता है जहाँ प्रतिभा हारती है और सिस्टम चूक जाता है?

आज की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि सरकारी भर्ती प्रणाली धीरे-धीरे एंट्री सिस्टम बनती जा रही है, न कि करियर सिस्टम। न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं होने के बावजूद, चपरासी, क्लर्क और लोअर ग्रेड की नौकरियों के लिए डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस और एमबीए जैसे उच्च शिक्षित उम्मीदवार आवेदन कर रहे हैं। यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि एक विकृत रोजगार संरचना का संकेत है। इन उम्मीदवारों का उद्देश्य उस पद पर स्थायी रूप से कार्य करना नहीं होता, बल्कि किसी भी तरह सरकारी तंत्र में प्रवेश लेना होता है, ताकि आगे चलकर वे बेहतर पदों के लिए प्रयास कर सकें।

यहीं से शुरू होती है वह समस्या, जो पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही है – जॉइन-ट्रेन-छोड़ संस्कृति। एक अभ्यर्थी पहले एक पद ग्रहण करता है, फिर कुछ महीनों या वर्षों में दूसरे, अधिक आकर्षक पद पर चयनित होकर उसे छोड़ देता है। यह अब अपवाद नहीं, बल्कि एक स्थापित प्रवृत्ति बन चुकी है। इसका सीधा परिणाम यह होता है कि एक ही व्यक्ति द्वारा कई पदों पर चयन और त्याग होता है, जिससे कई पिछली सीटें अनावश्यक रूप से खाली हो जाती हैं।

ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोगों का सपना सिर्फ आईएएस बनने का होता है , लेकिन उनका सिलेक्शन आईपीएस, आईआरएस या अन्य अधीनस्थ सेवाओं में होता है, तो वो उसको भी ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में वह बार-बार आईएएस की परीक्षा देते रहते हैं और जब अंत में उनका आईएएस में सिलेक्शन हो जाता है तो अपनी तमन्ना पूरी होने पर वो पिछला पद छोड़ देते हैं।उनके इस कृत्य की वजह से पिछली दो तीन सीटें खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग रोजगार से वंचित रह जाते हैं, कायदे में जिनको वह पुरानी सीट मिलनी चाहिए थी। यदि हम आधिकारिक आंकड़ों को देखें, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती है। संसद में प्रस्तुत हालिया आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में लगभग 9.6 लाख से अधिक पद रिक्त रहे हैं। कुछ स्वतंत्र विश्लेषणों में यह संख्या 10 लाख के आसपास भी बताई गई है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और अन्य एजेंसियों के अनुभव बताते हैं कि 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक चयनित उम्मीदवार अंतिम रूप से सेवा में नहीं टिकते – या तो वे जॉइन नहीं करते या जॉइन करने के बाद जल्द ही सेवा छोड़ देते हैं। राज्यों की स्थिति इससे भी अधिक असंतुलित है। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 लाख पद, राजस्थान में 1.5 से 2 लाख पद, और बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में भी लाखों पद लंबे समय तक रिक्त रहते हैं। यह केवल भर्ती में देरी नहीं, बल्कि पोस्ट-सेलेक्शन अस्थिरता का स्पष्ट संकेत है।

जब कोई उम्मीदवार चयनित होता है, तो सरकार उस पर प्रशिक्षण, वेतन, आवास और अन्य सुविधाओं के रूप में लाखों रुपये खर्च करती है। कई मामलों में यह खर्च प्रति उम्मीदवार 2 से 10 लाख रुपये या उससे अधिक होता है। उच्च सेवाओं में यह लागत और भी अधिक होती है। यह पैसा करदाताओं का होता है। लेकिन जब वही उम्मीदवार कुछ समय बाद सेवा छोड़ देता है, तो यह पूरा निवेश संक लागत बन जाता है – जिसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता।

इससे भी बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब वह सीट खाली रह जाती है और उसी भर्ती वर्ष की प्रतीक्षा सूची को सक्रिय नहीं किया जाता। यह स्थिति डेड सीट कहलाती है – जहाँ पद मौजूद है, बजट मौजूद है, जरूरत मौजूद है, लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा। जिला स्तर पर इसका असर बेहद गंभीर होता है – स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, प्रशासन में अधिकारी नहीं – और इसका सीधा नुकसान आम नागरिक को उठाना पड़ता है। यहीं लास्ट कट-ऑफ की अवधारणा पूरी तरह सवालों के घेरे में आ जाती है। कट-ऑफ एक तकनीकी सीमा है, लेकिन जब चयनित उम्मीदवार सेवा में नहीं टिकते और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलता, तो यह कट-ऑफ न्याय नहीं, बल्कि अन्याय का उपकरण बन जाती है। जो उम्मीदवार केवल कुछ अंकों से पीछे रह गए थे, वे केवल इसलिए बाहर रह जाते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें अवसर देने में विफल रहता है। यह न केवल प्रतिभा का नुकसान है, बल्कि सिस्टम की नैतिक विफलता भी है। इस पूरी समस्या को यदि चार बिंदुओं में समझें, तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है –

(1) एक ही व्यक्ति द्वारा कई पदों पर चयन और त्याग

(2) सरकारी संसाधनों – वेतन, प्रशिक्षण, समय – का दुरुपयोग

(3) प्रतीक्षा सूची के योग्य उम्मीदवारों को अवसर न मिलना

(4) चयन प्रक्रिया में देरी और रिक्त पदों की बढ़ती संख्या

अब सवाल यह है कि समाधान क्या है? और क्या केवल सुधार से काम चलेगा या एक कठोर नीति की आवश्यकता है? सबसे पहला और सबसे प्रभावी समाधान है – रोलिंग वेटलिस्ट प्रणाली का अनिवार्य क्रियान्वयन। इसका सिद्धांत बेहद सरल है – जिस भर्ती वर्ष की सीट खाली होती है, उसे उसी वर्ष की प्रतीक्षा सूची से 12-18 महीने के भीतर भर दिया जाए। यह कोई जटिल सुधार नहीं है, बल्कि एक बुनियादी प्रशासनिक जिम्मेदारी है, जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया है। यदि यह प्रणाली लागू होती है, तो डेड सीट की समस्या लगभग समाप्त हो सकती है और अंतिम कट-ऑफ से थोड़ा पीछे रह गए उम्मीदवारों को वास्तविक न्याय मिल सकता है। लेकिन केवल रोलिंग वेटलिस्ट पर्याप्त नहीं है। अब समय आ गया है कि सरकार एक कठोर और स्पष्ट नीति ढांचा तैयार करे। उदाहरण के लिए – जब कोई अभ्यर्थी पहली बार किसी सरकारी पद के लिए आवेदन करे, तो वह यह लिखित घोषणा दे कि वह उसी पद के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा।

इसके साथ ही न्यूनतम सेवा बांड (3-5 वर्ष) लागू किया जाना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि से पहले सेवा छोड़ता है, तो उससे प्रशिक्षण और अन्य खर्चों की वसूली की जाए। इसी तरह, क्रॉस-सर्विस परीक्षाओं के लिए सीमित प्रयास और कूल-ऑफ अवधि भी तय की जानी चाहिए, ताकि उम्मीदवार बिना जिम्मेदारी के बार-बार सिस्टम का उपयोग न कर सकें। नीति-निर्माण के स्तर पर पारदर्शिता भी अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न विभागों में डेटा बिखरा हुआ है – कितने पद भरे गए, कितने उम्मीदवारों ने जॉइन नहीं किया, कितनों ने सेवा छोड़ी, कितनी सीटें खाली रह गईं – इन सभी का समेकित और नियमित प्रकाशन नहीं होता। यदि यह डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो, तो न केवल समस्या का सही आकलन हो सकेगा, बल्कि नीति-निर्माण भी अधिक डेटा-आधारित और प्रभावी होगा। इस पूरे मुद्दे का एक महत्वपूर्ण नैतिक आयाम भी है, जिसे अक्सर नजर अंदाज कर दिया जाता है। क्या यह उचित है कि कोई व्यक्ति अपने करियर के लिए बार-बार अवसर ले और फिर छोड़ दे, जबकि कोई दूसरा योग्य उम्मीदवार उसी अवसर के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा हो? यह न केवल संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि उन उम्मीदवारों के साथ भी अन्याय है, जिनके लिए वह नौकरी अंतिम लक्ष्य है। यदि कोई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, तो उसे सीधे उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए, न कि अन्य पदों को बैकअप प्लान के रूप में उपयोग करना चाहिए। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नीति और नैतिकता दोनों की विफलता है। यदि इसे समय रहते नहीं सुधारा गया, तो यह न केवल प्रशासनिक क्षमता को कमजोर करेगा, बल्कि युवाओं के बीच सिस्टम के प्रति विश्वास को भी खत्म कर देगा। आज सरकार, भर्ती एजेंसियों और नीति-निर्माताओं के सामने एक सीधा प्रश्न खड़ा है – क्या वे एक ऐसी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, जहाँ सीटें खाली रहें, संसाधन बर्बाद हों और योग्य उम्मीदवार बाहर रह जाएँ? या वे एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहते हैं, जहाँ हर सीट भरे, हर अवसर का सही उपयोग हो और हर योग्य व्यक्ति को उसका अधिकार मिले?

रोलिंग वेटलिस्ट + न्यूनतम सेवा प्रतिबद्धता + कूल-ऑफ नीति + पारदर्शी डेटा सिस्टम

अब आवश्यकता केवल इच्छाशक्ति की है। क्योंकि जब तक नीति नहीं बदलेगी, तब तक कट-ऑफ के उस पार खड़े लाखों युवाओं के लिए न्याय केवल एक सपना ही बना रहेगा।

–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।

राशिफल शुक्रवार 3 अप्रैल, 2026

पंडित अनिल शर्मा

वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2083, चित्रा नक्षत्र सायं 7:25 तक, व्याघात योग दिन 2:08 तक, कौलव करण प्रातः 8:43 तक, चन्द्रमा आज प्रातः 6:24 से तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मीन, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-मेष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज राजयोग प्रातः 8:43 से सायं 7:25 तक है। आज एकलिंगजी पाटोत्सव उदयपुर में है। आज गुड फ्राइडे है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:52 तक, लाभ-अमृत 7:52 से 10:58 तक, शुभ 12:30 से 2:05 तक, चर 5:08 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:20, सूर्यास्त 6:41

मेष
परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास बना रहेगा। आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। आज अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। आज व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा।

कर्क
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। आज समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है।

मीन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा।

अटल निश्चय से उपजे विराट संकल्प की बदौलत प्रगति के विकास पथ पर सवार राजस्थान

रामसिंह

विकसित भारत 2047 के गन्तव्य तक पहुंचाने के लिए पीएमजीएसवाई महत्वपूर्ण बिन्दु भी है, साधन भी है। इस योजना के क्रियान्वयन से पूर्व राज्य के हजारों गांवों में हर मानसून में जन जीवन ठहर सा जाता था। पुराने और जर्जर पुल बाढ़ के पानी में डूब जाते थे, जिससे मरीज, विद्यार्थी और किसान अस्पतालों, स्कूलों और बाज़ारों जैसी सुविधाओं से कट जाते थे। इसी जरूरत को समझते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रूप में भारत के असंबद्ध गांवों को सड़क से जोड़ने की मजबूत नींव रखी। सामान्य क्षेत्र की 500 से अधिक एवं मरूस्थलीय तथा आदिवासी क्षेत्र की 250 से अधिक आबादी की बसावटों को सर्वकालिक पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा आगे चलकर इसमें प्रमुख ग्रामीण सड़कों का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण करने का लक्ष्य भी सम्मिलित किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बस्तियों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ना है।

इसी लक्ष्य की प्राप्ति में राजस्थान ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गत 25 वर्षों में प्रदेश में 75 हजार किमी. सड़कों का निर्माण किया गया एवं 15983 बसावटों/ गांवों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। प्रथम चरण में प्रदेश में लगभग 12086 करोड़ रूपये की लागत से 49 हजार 730 किमी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण कर 15 हजार 983 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ा गया। इसके साथ ही 14043 किमी. सड़कों का चौडाईकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया तथा 26 पुलों का निर्माण करवाया गया।

जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता गया, चयनित थ्रू रूट्स और ग्रामीण सड़क नेटवर्क को अधिक मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई। योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में करोड़ रुपये की लागत से 3 हजार 468 किमी. लम्बाई की 401 सड़कों का चौडाईकरण सुदृढ़ीकरण कार्य करवाया गया तथा 6 पुलों का निर्माण करवाया गया। योजना के तीसरे चरण में भी मौजूदा मार्गों व ग्रामीण संपर्क मार्गों को उन्नत किया गया ताकि बसावटों से कृषि बाजारों, कॉलेजों, अस्पतालों, अन्य किसान संबंधित उद्यमों तक सुगम एवं त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित की जा सकें। इस चरण में अब तक प्रदेश में 4 हजार 113 करोड़ रुपये की लागत से 8 हजार 584 किमी. की 912 सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण करवाया गया तथा 36 करवाया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत हैं।

पीएम जनमन- इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में देश के 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए पीएम-जनमन योजना का शुभारम्भ किया गया। प्रदेश में इस योजना के तहत बारां जिले की शाहबाद व किशनगंज ब्लॉक की सहरिया जनजाति बहुल 100 से अधिक आबादी की 31 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। इसके तहत् लगभग 33.48 करोड़ की लागत से 35 किमी. सड़क निर्माण कर 13 बसावटों को सड़के से जोड़ने का कार्य पूरा किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिरत है। चौथे चरण में प्रवेश- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीन चरण प्रदेश में पूरे हो चुके हैं ओर चौथे चरण का आगाज होने जा रहा है। चतुर्थ चरण में प्रदेश की 1216 बसावटों को ऑलवेदर पक्की सड़कों से जोड़ने व एक पुल के निर्माण के लिए बजट आ चुका है और निर्माण काम तेजी से प्रगति पर है। इस चरण की सड़कों व पुल की अनुमानित लम्बाई 3219 किमी. व लागत लगभग 2 हजार 89.37 करोड़ आंकी गई है। गौरतलब है कि चौथे चरण में 1638 बसावटों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना के चौथे चरण में प्रदेश की 1638 बसावटों को ऑलवेदर सड़कों से जोड़े जाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके प्रथम फेज में 1216 बसावटों के लिए सड़क व एक पुल का निर्माण करवाया जायेगा। प्रथम फेज में लगभग 2 हजार 89 करोड़ रूपये की लागत से 3219 किमी. नयी सड़कों का निर्माण करवाया जायेगा।

चौथे चरण के प्रथम बैच में अजमेर जिले में 7 किमी 60 मीटर लम्बी 5 सड़कों के लिए 4.80 करोड़ रू., अलवर में 2 किमी की 2 सड़क के लिए 2.88 करोड़, बालोतरा में 487 किमी लम्बाई की 161 सड़कों के लिए 280.13 करोड़ रू.,बांसवाड़ा में 90.1 किमी लम्बी 50 सड़कों के लिए 6067 लाख रू.,बारां में 36 किमी 12 सड़कों के लिए 2515.25 लाख, बाड़मेर में 748.1 किमी लम्बी 261 सड़कों के लिए 52377.28 लाख रू. ब्यावर में 4.8 किमी लम्बी 3 सड़कों के लिए 467 लाख रू. बजट उपलब्ध है।

–रामसिंह, पीआरओ,
सानिवि